प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा मिली- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आतंकवाद व नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही की जा रही है

जयपुर, 20 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विजयादशमी का पर्व केवल रावण वध का स्मरण करने का अवसर नहीं, बल्कि समाज में व्याप्त बुराइयों और कुरीतियों को समाप्त करने का संकल्प लेने का भी पर्व है।

मुख्यमंत्री मंगलवार को जयपुर के आदर्श नगर में विजयादशमी के अवसर पर आयोजित रावण दहन महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास के साथ,

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के आदर्श नगर में विजयदशमी पर आयोजित रावण दहन महोत्सव को संबोधित किया।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के आदर्श नगर में विजयादशमी के अवसर पर आयोजित रावण दहन महोत्सव में शामिल हुए।

सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन का ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। अयोध्या में श्रीरामलला की प्राण-प्रतिष्ठा, काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्विकास, उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण और सोमनाथ की गौरवशाली विरासत के स्मरण जैसे कार्यों ने देश की सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा प्रदान की है। उन्होंने आगे कहा कि इसी प्रकार, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। वहीं, नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई से देश में शांति और सुरक्षा का वातावरण मजबूत हुआ है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने श्रीराम मंदिर में राम दरबार के दर्शन और पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और सुख-समृद्धि की कामना की।

यूसुफ पठान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परिस्थितियाँ भी बदलती रहीं। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण वाले वडोदरा नगर निगम ने 2024 में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीतने के तुरंत बाद पठान को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया था। पठान ने इस नोटिस को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

हाल के महीनों में न्यायिक जाँच तेज होने के साथ यह कानूनी लड़ाई एक अहम मोड़ पर पहुँच गई। उच्च न्यायालय ने हाल ही में जमीन पर कब्जे को लेकर कड़ी नाराजगी जताई और सवाल उठाया कि अंतिम आवंटन तथा उचित वित्तीय मंजूरी के बिना नगर निगम की जमीन का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है।

अदालत की सख्त चेतावनियों और संभावित जुर्माने को देखते हुए, क्रिकेटर के कानूनी प्रतिनिधियों ने उच्च न्यायालय में लंबित अपीलें बिना किसी शर्त के वापस लेने का फैसला किया। इससे प्रशासन को इस मामले पर नए सिरे से विचार-विमर्श करने का रास्ता मिल गया।

पटाखा मुक्त ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संस्थानों, आवासीय कल्याण संघों और स्थानीय समुदायों तक पहुंच बनाई जाएगी। इसमें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत शामिल 130 शहरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

'लोकतंत्र में समस्याएं तो बनी रहेंगी और इस कारण से आंदोलन भी होंगे'

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने दशहरा उद्बोधन में यह भी कहा कि विरोध प्रदर्शनों से समाज में विभाजन पैदा नहीं होना चाहिए

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर। विरोध प्रदर्शन किसी समस्या को लेकर लोगों को एकजुट कर सकते हैं, लेकिन जब आंदोलन ही समाज में विभाजन का कारण बनने लगें, तो क्या होगा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को नागपुर में विजयादशमी के अपने संबोधन में इस सवाल पर बात की।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन होना स्वाभाविक है, लेकिन उनका उद्देश्य समस्याओं का समाधान करना होना चाहिए, न कि समाज में दूरियों या मतभेदों को और बढ़ाना।

उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब भारत में नीट-यूजी के प्रश्नपत्र लीक होने और हाल ही में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई है।

भागवत ने कहा, "समस्याएँ तो बनी रहेंगी। इन समस्याओं के कारण आंदोलन भी होंगे और लोकतंत्र में आंदोलन होना स्वाभाविक है। लेकिन आंदोलन किसलिए होने चाहिए? उनका उद्देश्य समाधान निकालना होना चाहिए।"

आरएसएस प्रमुख ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों के कारण दुश्मनी या समाज में विभाजन पैदा न हो, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सभी पक्षों की है। इसमें आंदोलन करने वाले समूह, सरकार, प्रशासन और राजनीतिक नेता शामिल हैं। उन्होंने कहा, "हमारी भावनाएँ कितनी भी तीव्र क्यों न हों, संविधान और कानून के तहत हमारे काम करने की कुछ सीमाएँ हैं। इसके अलावा, सभ्य सार्वजनिक आचरणों के नियमों के अनुसार भी, हमारी बातचीत और व्यवहार की कुछ सीमाएं तय हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे काम इन सीमाओं के दायरे में ही रहें।"

भागवत ने पश्चिमी देशों के बारे में बात करते हुए आरोप लगाया कि भारत को कमज़ोर करने की कोशिश करने वाली ताकतें देश में अस्थिरता पैदा करने और आंतरिक घटनाक्रमों को प्रभावित करने के लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रही हैं।

मोहन भागवत ने आरोप लगाया है कि वैश्विक ताकतें सत्ता परिवर्तन की कोशिशों के जरिए भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि देश में ऐसी कोशिशें पहले से ही चल रही हैं और इन्हें राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित, सत्ता के भूखे नेता समर्थन दे रहे हैं।

छात्र आंदोलन का असर सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने तथा स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए मिले संवैधानिक अधिकारों का पर्याप्त सम्मान किया गया? यह घटनाक्रम यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के लंबे समय से चल रहे अभियान की पृष्ठभूमि में सामने आया है। इसके साथ ही, भारत खुद को विकासशील देशों की एक प्रमुख आवाज़ और एक अधिक समावेशी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के समर्थक के रूप में स्थापित करने का भी प्रयास कर रहा है। भारत का तर्क है कि सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना, जो 1945 की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को दर्शाती है, आज की वैश्विक शक्ति और जनसंख्या वितरण का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती है। नई दिल्ली ने अपनी आर्थिक ताकत, राजनयिक पहुंच, बहुपक्षीय संस्थाओं में भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व विकास में अपनी भूमिका के ज़रिए अपना पक्ष मज़बूत करने की कोशिश की है। हालाँकि, स्थायी सदस्यता का मुद्दा अंततः अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और संस्थागत सुधार से जुड़ा है, यह कोई ऐसा इनाम नहीं है, जो केवल किसी देश के घरेलू राजनीतिक रिकॉर्ड के आधार पर दे दिया जाए। सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए यूएन चार्टर में बदलाव की ज़रूरत होगी, जिसमें मौजूदा स्थायी सदस्यों की मंज़ूरी और यूएन के सदस्य देशों द्वारा ज़रूरी अनुसमर्थन शामिल है। फिर भी, लोकतांत्रिक शासन और मौलिक अधिकारों का सम्मान उस व्यापक अंतरराष्ट्रीय संदर्भ का हिस्सा हैं, जिसके आधार पर वैश्विक नेतृत्व के लिए भारत के दावों का आकलन किया जाता है। प्रभावशाली विदेशी मीडिया में की गई आलोचनात्मक रिपोर्टिंग, भारत को लोकतांत्रिक शासन के एक आदर्श के रूप में पेश करने के प्रयासों को मुश्किल बना सकती है। ऐसा तब और भी होता है, जब आरोप छात्रों, पत्रकारों और चुनावी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने वाले नागरिकों के साथ किए गए व्यवहार से जुड़े हों। इन बातों का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। अख़बारों में छपी आलोचनात्मक रिपोर्टों को विदेशी सरकारों का सामूहिक फ़ैसला नहीं माना जा सकता, और न ही इससे यह साबित होता है कि भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं ने काम करना बंद कर दिया है। भारत का संवैधानिक ढांचा, प्रतिस्पर्धी चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका और सक्रिय नागरिक समाज, इसके व्यापक मूल्यांकन के महत्वपूर्ण हिस्से बने हुए हैं। लेकिन अगर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोपों की विश्वसनीय जांच नहीं होती है, पत्रकारों पर पाबंदियां बनी रहती हैं, या मतदाता सूची में बदलाव को लेकर उठने वाली चिंताओं का समाधान पारदर्शी तरीके से नहीं किया जाता है, तो इससे भारत की छवि को और ज्यादा नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए भारत के सामने चुनौती सिर्फ़ अपने ख़िलाफ़ आने वाली अंतरराष्ट्रीय ख़बरों का जवाब देने की नहीं है, बल्कि यह साबित करने की है कि उसकी लोकतांत्रिक संस्थाएं असहमति को जगह दे सकती हैं, प्रेस की रक्षा कर सकती हैं, और नागरिकों के अधिकारों से जुड़े विवादों में प्रभावी समाधान प्रदान कर सकती हैं। जैसे-जैसे नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में अपनी अधिक प्रभावी भूमिका की मांग कर रही है, उसके तर्कों की विश्वसनीयता न केवल उसकी आर्थिक और रणनीतिक ताकत पर निर्भर करेगी, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेगी कि वह विश्व मंच पर जिन लोकतांत्रिक सिद्धांतों की वकालत करती है, उन्हें कितनी निरंतरता के साथ लागू करती है।

प्रियंका गांधी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सीटों की सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा, इस सूची में पार्टी के प्रमुख नेताओं जैसे अजय राय, अजय लल्लू, सुप्रिया श्रीनेत और नदीम जावेद से जुड़ी सीटें भी शामिल हैं। कांग्रेस अमेठी, रायबरेली और सहारनपुर की उन सीटों पर भी अपना दावा करना चाहती है, जहाँ फिलहाल समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इसके अलावा, पार्टी की नज़र लगभग एक दर्जन ऐसी सीटों पर भी है, जहाँ समाजवादी पार्टी जीती थी।

यूपी के सभी जिलों में सरदार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समुदाय की अच्छी-खासी मौजूदगी है और माना जाता है कि ये लगभग 48-50 विधानसभा क्षेत्रों में काफी प्रभाव रखते हैं। वर्तमान में, राज्य विधानसभा में सबसे ज्यादा कुर्मी विधायक, (लगभग 40 कुर्मी विधायकों में से करीब 27) विधायक भाजपा के पास हैं। इसके अलावा, पार्टी के संगठन में भी कुर्मी समुदाय के लोगों को अहम पदों पर रखा गया है और कुर्मी-बहुल अपना दल (एस) के साथ भाजपा का गठबंधन भी है। हालांकि, कुछ सर्वे बताते हैं कि 2019 से 2024 के बीच कुर्मी समुदाय के एनडीए के समर्थन में कुछ कमी आई है, इसलिए अब इस रिश्ते को फिर से मजबूत करने की कोशिशें की जा रही हैं।

इस पहल के जरिए, भाजपा का लक्ष्य राज्य में लंबे समय से चली आ रही अपनी 'सामाजिक गठबंधन' रणनीति के तहत, गैर-यादव ओबीसी समुदायों को और अधिक मजबूती से अपने साथ जोड़ना है।

राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव की पटेल की विरासत को समकालीन राजनीति से जोड़कर, पार्टी इन समूहों के बीच प्रतीकात्मक और संगठनात्मक लाभ हासिल करना चाहती है। साथ ही, वह विभाजनकारी जाति - राजनीति के खिलाफ अपने नैरेटिव को और मजबूत करना चाहती है। विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी द्वारा इस कदम के जवाब में "पीडीए" (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) अभियान को तेज किये जाने देने की उम्मीद है। वे सामाजिक न्याय, गैर-यादव ओबीसी समुदायों को अधिक प्रतिनिधित्व देने, और किसानों, रोजगार तथा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर मौजूदा सरकार के कामकाज की आलोचना करने पर जोर देंगे। समाजवादी पार्टी पहले ही कुर्मी समुदाय के प्रतिनिधित्व को बढ़ा चुकी है और वह आगे भी इस समुदाय के नेताओं को अहमियत दे सकती है, साथ ही ओबीसी के मुद्दों पर भाजपा की गंभीरता पर सवाल उठा सकती है।

कांग्रेस संभवतः जाति जनगणना की मांग को जोर-शोर से उठाएगी और राष्ट्र-निर्माण में अपने ऐतिहासिक योगदान को रेखांकित करेगी। वहीं, छोटे दल किसी भी विपक्षी गठबंधन में सीटों के बड़े हिस्से की मांग कर सकते हैं या अपने स्वतन्त्र एवं निर्दलीय अस्तित्व पर जोर देने के प्रयास कर सकते हैं।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, **जयपुर कार्यालयः** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34, **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः 2386031, 2386032,फैक्सः0744-2386033, **उदयपुर कार्यालयः** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालयः**-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोनः 2627612, फैक्सः0145-2624665, **जालौर कार्यालय :-** प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्सः 02973-226424, **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908